भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1592
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

हरित इस्पात उत्पादन

1592 श्री हर्ष वर्धन श्रृंगलाः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निम्न-कार्बन या हरित-इस्पात उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएँ कौन-कौन सी हैं;

(ग) विकार्बनीकरण के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं;

(घ) इसमें सार्वजनिक और निजी इस्पात संयंत्रों की भागीदारी कितनी-कितनी है; और

(ङ) इसका भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन रूपरेखा में अपेक्षित योगदान कितना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): निम्न कार्बन या ग्रीन-स्टील उत्पादन हेतु वर्तमान क्षमता सहित वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य (नेट जीरो) लक्ष्य सहित इस्पात क्षेत्र के ग्रीन ट्रांज़िशन के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का विवरण, इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए अनुमोदित पायलट परियोजनाएं और सार्वजनिक तथा निजी इस्पात संयंत्रों की भागीदारी निम्नानुसार है:

(i) इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु दिनांक 23.12.2024 को ग्रीन स्टील के वर्गीकरण को अधिसूचित किया है। ग्रीन स्टील वर्गीकरण की रूपरेखा के तहत, अब तक 43 इस्पात इकाइयों को 'ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र' प्रदान किए गए हैं। ये सभी इस्पात संयंत्र निजी क्षेत्र के हैं। इन 43 इस्पात इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता 11.6 मिलियन टन प्रति वर्ष है जो 7.1 मिलियन टन प्रति वर्ष ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रही हैँ।

(ii) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत, इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस्पात मंत्रालय को वित्त वर्ष 2029-30 तक 455 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र केउद्यम (सीपीएसई) और तीन निजी इस्पात संयंत्रों सहित चार इस्पात संयंत्रों को चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

(iii) इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्य बलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है।

******